अनौपचारिक अनुवाद

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन - 109 वां सत्र, 2021

म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी और मौलिक अधिकारों के सम्मान के लिए संकल्प (19 जून 2021)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सामान्य सम्मेलन,
109 वें सत्र की बैठक,

म्यांमार में मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र और कानून के सम्मान के लिए ILO की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को याद करते हुए,

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट द्वारा नागरिक सरकार को हटाने, 1 फरवरी 2021 से आपातकाल की स्थिति और अन्य घटनाओं की घोषणा, जैसे की ट्रेड यूनियनवादियों और अन्य लोगों के खिलाफ, जो अपना शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे है, उनके खिलाफ मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत, धमकी, और हिंसा के कृत्यों सहित, और साथ-साथ कारखानों और अन्य कार्यस्थलों के विनाश पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए

आठ सौ से अधिक लोगों की मौत पर खेद व्यक्त करते हुए, जिसमे ट्रेड यूनियनवादियों भी शामिल जो की सैन्य तख्तापलट के विरोध में अपने शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे,

गंभीर रूप से चिंतित है कि पुलिस और सेना ने ट्रेड यूनियन कार्यालयों और घरों पर छापें मारें, ट्रेड यूनियनवादियों और उनके परिवारों को परेशान किया और धमकी दी और उनके हड़तालों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भागीदारी के प्रतिशोध में ट्रेड यूनियन नेताओं को हिरासत में रखा और वांछित सूची में रखा जो की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली और नागरिक शासन और लोकतंत्र में संक्रमण की निरंतरता और श्रम अधिकारों सहित मानव अधिकारों के उल्लंघन का अंत की मांग कर रहे थे,

1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद, नियोक्ताओं की क्षमता के लिए गंभीर जोखिमों को स्वीकार करते हुए, अच्छे काम और उनके उद्यमों की स्थिरता प्रदान करने के लिए,

यह याद करते हुए कि शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता और राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता के अभ्यास के लिए आवश्यक है और सभी सदस्य राज्यों का दायित्व है कि वे पूरी तरह से, कानून और व्यवहार में, उन सम्मेलनों को लागू करें जिन्हें उन्होंने स्वेच्छा से अनुसमर्थित किया है,

सेना द्वारा बंधुआ मज़दूरी के उपयोग, वह क्षेत्र शामिल है जहाँ टकराव और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जैसे की रोहिंग्या, विशेष रूप से देश भर में संघर्ष बढ़ने पर गहरी चिंता के साथ ध्यान देते हुए,

यह भी ध्यान में रखते हुए कि देश भर में बिगड़ती मानवीय स्थिति विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में, और जहाँ मानवीय पहुंच की कमी है, बड़े पैमाने पर श्रम अधिकारों और मानवाधिकारों के प्रभावी अभ्यास के लिए खतरा पैदा करती है,

रोहिंग्या सहित धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के लोगों के लिए जबरन विस्थापन और नौकरियों और आजीविका के अवसरों तक पहुंच की कमी के बढ़ते जोखिमों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए,

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और लोकतंत्र में वापसी की मांग के लिए कार्रवाई में लगे व्यापारिक समुदाय सहित श्रमिकों, यूनियनों और आम जनता के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए,

1. म्यांमार को आह्वान:

(a) म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक शासन को बहाल करना, और - एक बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार बहाल हो जाने के बाद - सिविल सेवा कार्मिक कानून, श्रम विवादों के निपटान कानून और श्रम संगठन कानून में बिना किसी देरी के संशोधन करना जो सगठन की स्वतंत्रता और सम्मेलन आयोजित करने के अधिकार का संरक्षण कन्वेंशन, 1948 (नंबर 87) म्यांमार द्वारा अनुसमर्थित के संगत हो;

(b) श्रमिकों, नियोक्ताओं और उनके संबंधित संगठनों और सामान्य आबादी के खिलाफ सेना द्वारा सभी हमलों, धमकियों और धमकी को रोकना, जिसमें विरोध गतिविधियों में उनकी शांतिपूर्ण भागीदारी के साथ-साथ रोहिंग्या जैसे धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी शामिल है और तुरंत और बिना शर्त निरोध से रिहा करना और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों के खिलाफ किसी भी आरोप को वापस लेना;

(c) मानव अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करना और मौलिक सिद्धांतों और काम पर अधिकारों की बहाली सुनिश्चित करना;

(d) कन्वेंशन नंबर 87 का सम्मान करें और सुनिश्चित करें कि श्रमिकों और नियोक्ता, हिंसा, मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी से मुक्त स्वतंत्रता और सुरक्षा के माहौल में संघटन के अधिकारों की स्वतंत्रता का प्रयोग करने में सक्षम हो;

(e) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता को कम करने वाली और नागरिक सरकार को हटाने के बाद जारी किए गए किसी भी उपाय या आदेश, या लगाए गए अतिरिक्त उपायों को निरस्त करें और श्रमिकों, नियोक्ताओं और उनके संबंधित संगठनों की स्वतंत्रता को स्वतंत्र रूप से और उनकी गतिविधियों को करने के लिए प्रतिबंधित करने वाले उपायों को निरस्त करें, बिना धमकी या नुकसान का खतरा;

(f) सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सुरक्षित और अबाधित मानवीय पहुंच सुनिश्चित करें।

2. सिफारिश करता है कि संयुक्त राष्ट्र, अन्य बहुपक्षीय निकायों, क्षेत्रीय समूहों और संवादों और द्विपक्षीय जुड़ाव सहित सदस्य राज्य म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली का समर्थन करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक शासन की त्वरित बहाली को आगे बढ़ाने और म्यांमार में लोकतंत्र में संक्रमण की निरंतरता को आगे बढ़ाने में श्रमिकों और नियोक्ता संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए।

3. अनुरोध है कि शासी निकाय के 341वें सत्र (मार्च 2021) के निर्णयों के साथ इस संकल्प के कार्यान्वयन पर शासी निकाय द्वारा आगे किसी भी विचार के लिए पालन किया जाए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 110वें सत्र के संबंध में भी शामिल है।